



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—पाँड 1  
PART I—Section 1

प्रतिथक्षर से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

पं० 208]  
No. 208]

नई दिल्ली, भंगलधार, दिसम्बर 21, 1982/अग्रहायण 30, 1904  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1982/AGRAHAYANA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह बलम संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.*

### आणिय मंत्रालय

#### नियति व्यापार नियंत्रण

सार्वों सूचना सं० 40 ई० टी० सी० (पी० एन) 82

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर 1982

विषय:- खुले सामान्य लाईसेंस 3 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों आस्ट्रिया, फिनलैंड को पीशाओं और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के 1-1-1983 से 31-12-1983 तक नियति के लिए योजना।

मिसिस सं० 2 / 54 / 82-ई० —प्रमुख सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक सूचना सं० ई० टी० सी० (पी० एन) / 82 दिनांक 18 दिसम्बर 1982 के क्रम में है और सैयार पीशाओं और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कनिष्ठ मर्दों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, कांग, हॉली, बेनिलक्स, यू० के, आयरलैंड गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया कनाडा और फिनलैंड को। 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर 1983 तक को अवधि के लिए विवरों से संबंधित है।

2. योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरण : जब तक अन्यथा रूप से नियति न दिए जाए तो परिधान नियति संवर्धन परिषद, नई दिल्ली नियति हकदारियों का नियतन करेगी और इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी पौशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों का आवश्यक प्रमाणन करेगों किन्तु मिलाई से बुने हुए ऊनो वस्त्रों की हकदारी का नियतन ऊन और ऊनी सामान नियति संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। लेकिन, सलाई से बुने हुए ऊनो वस्त्रों के मामले में आवश्यक प्रमाणन परिधान नियति संवर्धन परिषद द्वारा किया जाना रहेगा। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों को श्रेणियों की सूचियां परिधान नियति संवर्धन परिषद और ऊन ऊनी सामान नियति संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध हैं। सरकार को यह प्रतिकार होगा कि वह योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा उचित समझे परिवर्तन करेगी।

3. खंडों के लिए आवश्यक : (i) पहले आए सो पहले पाए के छोटे-छाटे आदेशों और केन्द्रीय राज्य नियम पद्धतियों के मामलों में, जहां कहीं आवंटन के लिए हृषकरघा और मिल निमित वस्त्रों को श्रेणियों को मिलाया जाता है तो

वहाँ हथकरधा और मिल निर्मित / विजली के करघे  
में नैयार बिए था अन्धा था अनुपा । 1 होगा । विदेशी  
मार्गो और नियत हकदारियों के उपयोग को प्रवृत्ति पर  
निर्भर करन हुए सरकार को इस अनुपात में परिवर्तन करने  
का पर्वता ।

(2) जहा कही आवटन के लिए सलाई में बुने हुए वस्त्रों को बुने हुए वस्त्रों के साथ मिलाया जाता है तो वहा उपलब्ध मात्रा का 10 प्रतिशत मलाई में बुने हुए वस्त्रों के लिए आरक्षण रखा जाएगा।

(3) पहले आग मा पहले पाए के छोटे-छोटे श्रादिशो और केन्द्रीय / राज्य निगम पद्धतियों के मास्ते मे अन्तिम तारीख को वज्चों को पोषाको के लिए आरक्षण उस तारीख को सभी श्रेणियों मे उपलब्ध मावा का 10 प्रतिशत होगा।

(4) उनी पाणिको के मान्त्रे में आरभण विचिह्नित श्रेणियों में उपलब्ध मात्रा के अनुसार होगा। इसकी घाषणा वस्त्र आपका द्वारा की जाएगी।

४ धीमी गति वाली मदे .- पहले से ही धोषित मार्गदर्शनों में आशिक आशाधन करने पर धीमी गति वाली मदों के भास्मों में निष्टलिखित और मार्गदर्शन लाग जाए ।

११० प्रतिशत निर्यात शर्करा के लिए विभिन्न राज्यों के उत्पादन एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से लगभग ८५% लघु आदेश की पद्धति के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। चाहे वे १ जुलाई १९८२ की या इसके बाद परिवान निर्यात संबंधित परिषद के पास पंजीकृत किए गए हों।

(2) केन्द्रीय / राज्य निगमा और पहले आए भी पहले पाए के छोटे-छोटे आदेश की पद्धतियों के मामले में धीमी गति और मद्दों के लिए पोतलदान की अवधि सार्वजनिक सूचना स० 37-ई० टी० सी० (पी० एन) / 82, दिनांक 18 सितम्बर 1982 की कड़िका 4(1) में निहित अवधि के अनुसार ही होगी।

(3) ध्रीमी गति की मदों में बच्चों की पोशाकों के लिए अलग से न्यूनतम कीमत वस्त्र आयुक्त द्वारा निष्पारित की जा सकती है।

5. निर्यात हकदारी के प्रमाणन की वैधता अवधि।—  
उहले आए सो पहले पाए के छोटे-छोटे आदेश के पद्धति के  
आमले में जहाँ वैधता अवधि 30 दिन की होगी उसे  
छोड़कर निर्यात हकदारी का प्रमाणन 21 दिनों के लिए  
बीम होगा।

੭. ਪੇਣਾਂ ਦੀ ਨਿਕੋਧ. ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਡੀ ਆਂਦੇ ਤਨਕੀ ਜਲਦੀ :-

(1) भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता नियर्तिक पद्धति के सामले में एक नियर्तिक के लिए जनवरी—अप्रैल 1983 के दौरान पोतमधान को गई मादा के लिए हिसी किस्म के पेसगी करने या बैंक गारन्टी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। उसके लिए 30 अप्रैल, 1983 के बाद रोक.

रुद्धी गई नियानि हकदारियों के जहाज पर निशुल्क मूल्य की 10 प्रतिशत तक की सीमा के लिए पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के साथ निष्पादित बाड़ वो प्रस्तुत करना आवश्यक हा। ऐसे पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी का प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 मई, 1983 होगी। यदि 30 अप्रैल, 1983 के बाद पातलदान किए गए हो किन्तु पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने से पहले किए गए हो (जो 31 मई, 1983 से पहले होने चाहिए) तो उन्हें पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं होगी। 31 मई, 1983 तक जिस मात्रा का न तो पातलदान किया जाता है और न ही पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी के अन्तर्गत लिया जाता है तो उसे अधर्यापित किया गया समझा जाएगा। नियानि अपनी हकदारी या उसके भाग की ऐसी अधर्यापित मात्रा के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत नी गई पेशगी निक्षेप / बैंक गारन्टी 17 नोवेंबर 1983 को 30 अप्रैल, 1983 से अधर्यापित कर सकता है।

(2) पहले आए सो पहले पाए के प्राधार पर छोटे-छोटे आदेशों यीर केन्द्रोय / राज्य निगम प्रभालों के मामले में, नियर्थक को आवासित मात्रा के जहाज पर्यन्त नि-रुच मूल्य के 10 प्रतिशत को दर में वैल गारन्टी डाल समर्थित है। इनमें / गि । ५ बाट देना अनिवार्य होगा।

(3) धीमी गति की मद्दों के लिए जो इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी अभियास कराई गई है, जैसा ऊपर बताया गया है तो पेशगी / बैंक गारन्टी के स्थान पर वस्त्र आयुक्त हारा निर्धारित नाममात्र की ही पेशगी निषेध करना पड़ेगा।

(4) एक निर्यातिक जो उम्मको आबटित निर्यात हकदारी का 90 प्रतिशत तक का नियंत्रित भूतकालीन निष्पादन या विनियोग गिर्यातिक प्रणाली के अन्तर्गत सारे वर्ष के भीतर, या आबटन की श्रन्य प्रणालिया के अन्तर्गत विशिष्ट श्रवणि के भीतर नहीं करता है तो उम्मके पेशगी निदेप/वैक गारन्टी को जब्त नहीं किया जाएगा। एक निर्यातिक जो कम से कम 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत से कम का निर्यात करता है तो उम्मकी अनुपातिक जब्त की जाएगी। यदि निर्यात हकदारी आवंटन का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातिक पूरे पेशगी निदेप/वैक गारन्टी के जब्ती के लिए देनदार हगे। जहाँ कही आवश्यकता होगी यह अनिवार्य बाध्यता की शर्तों के अधीन होगा।

(5) केन्द्रीय / राज्य निगमों के उन मामलों में जहां उपयोग वैध अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम है तो नियांत्रिक को नियांत्रित हकदारी वर्षे के भीतर आगे की आवंटन अवधि के लिए वृद्धि प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सागत नियांत्रित हकदारी अवधि को समाप्ति के एक महोने के अन्दर-अन्दर भेज देने चाहिए। यह प्रावधान पहने थाएं सो पहले पाएं के माधार पर छोटे-छोटे आदेशों की प्रणाली के मन्तर्गत थोसी गति बानी मदों के मामले में लाग होगा। ऐसे मामलों में

नियर्तक को बेची हुई भावा के लिए सामान्य दर से दुगने पैशांग निक्षेप/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पड़ती है। पृष्ठ से नियर्त करने वें प्रत्यक्षता होने को लिखते हैं पैशांग निक्षेप/बैंक गारंटी पूर्ण को पूरी जब्त कर ली जाएगी।

(6) पैशांग व्यवहार (जिन्हे 1970 में हथकरघा आवंटित की गई है किन्तु जिन्होंने उसका उरा उपयोग नहीं किया है वे भविष्य में नियर्त हक्कदारी प्राप्त करने से वर्चित रहेंगे। और इसके अलावा इस सम्बन्ध में उन पर अन्य कारंबाड़ी की जा सकती है।

(7) पैशांग निक्षेप/बैंक गारंटी की जब्ती के खिलाफ अधिकारी:—याकृंदित नियर्त हक्कदारी का उपयोग न करने पर पैशांग निक्षेप/बैंक गारंटी की जब्ती के खिलाफ नियर्तियों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उचित स्पष्ट से विचार करने के लिए नियर्त हक्कदारी विधिविधि अनु भारी। अंतिम नियर्त हक्कदारी विधिविधि अनु भारी। नियर्त हक्कदारी की जब्ती के खिलाफ वस्त्र आयुक्त को जब्ती से सम्बन्धित पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधिक कर मरकता है। यसके प्रायुक्त प्रतिवेदन मिलने पर वित्ती शीघ्र सम्भव होगा, आत्मा निर्णय देंगे। यदि किसी भावने में नियर्त हक्कदार आयुक्त के विनियोग से सम्बन्ध नहीं है तो उस विधियों को बताने के लिए उपर्युक्त के 15 दिनों के भीतर नियर्त हक्कदार के विनियोग के लिए उपर्युक्त कर मरकता है। इतरी अपेक्षा वस्त्र विभाग द्वारा रोक रखी जाएगी अब उन पर भरकार द्वारा गठित अपेक्षा मिलित द्वारा विचार किया जाएगा।

(8) पहर्ला अक्टूबर, 1982 में उपनिवेश माला का विलयन:—हस भावंजिति गूनना और सार्वजनिक सूचना सं० 37-ईटीसी (पीएन)/82 दिनांक 18 अक्टूबर, 1982 में अन्यत दिए गए के बावजूद 1 अक्टूबर, 1982 को उत्तरव्यापकी बच्ची हुई सारी माला जो आवंटित स्थान पर है या अधिष्ठित है उसका सामान्य पूल में विलयन कर दिया जाएगा और वह पहले भारी सो पहले पाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों के प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों के लिए किसी आवश्यक के बिना आवंटित कर दी जाएगी।

(9) नियर्त हक्कदारी के आवंटन के लिए पैशांग:—वस्त्र आयुक्त, कम्पई नियर्त हक्कदारी के आवंटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन प्रतिदिन पूर्विकान का कार्य आरो रखेंगे। वस्त्र आयुक्त की अधिकारी में गठित समन्वय मिलित और सम्बन्धित नियर्त संबंधित परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर नीति के विचारन को पूरीरक्षा करेंगी। उन मामलों में, जिन में मन्त्रोदेश होगा, वस्त्र आयुक्त का नियर्त अतिम होगा।

(10) पत्तनों द्वारा विकासी:—(क) नियंत्रण के अधीन उत्पादें:—इस उद्देश्य के लिए मनोनीत परिधान नियर्त संबंधित परिषद अधिकारी द्वारा जारी किए गए नियर्त हक्कदारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पर और छोड़कर प्रेषण के लिए पोतलदान विलों

की प्रतुलिपि प्रति पर मोमा शुल्क प्राधिकारियोंद्वारा लदान के पत्तनों पर प्रमाणन के स्वापन के बाद ही पोतलदान अनुमेय होगा।

(ख) हथकरघा पोशाक: जहाँ तक नियंत्रण की नदनुस्पा मदों सभी हथकरघा पोशाकों की जागी आवंटित की गयी है तिन्होंने उसका उरा उपयोग नहीं किया है वे भविष्य में नियर्त हक्कदारी प्राप्त करने से वर्चित रहेंगे। और इसके अलावा इस सम्बन्ध में उन पर अन्य कारंबाड़ी भी की जा सकती है।

(ग) “भारतीय मदों” के अधीन आने वालों पोशाकों:—“भारतीय मदों” में सम्बन्ध में जो कि भारत की परम्परागत लोक जीवन से संबंधित हस्त-शिल्प वस्त्र उत्पादें हैं, उन्हें यूरोपीय अंतिम समुदाय के सदस्य देशों, अमरीका, फिनलैंड, शास्त्रिया और इगाडा को नियर्त के लिए सभी शुल्क सदस्य द्वारा पोतलदान विधि अनुपस्थिति विभाग अधिकारी वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर होंगी।

11(क) नियर्त प्रमाणपत्र उद्यगम प्रमाणपत्र और वीसा:—संबंधित द्विपक्षीय घरेलू समझौते के अधीन नियर्तियों अपेक्षित प्रमाणन परिधान नियर्त संबंधित गरिष्ठ अधिकारी इस सम्बन्ध में एतद्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय से जारी किए जाएंगे:

(1) यूरोपीय आधिकार गमुदाय

(क) नियंत्रण के अधीन सभी बुनी हुई पोशाक की मदों के लिए नियर्त प्रमाण-पत्र और उद्यगम के प्रमाण पत्र,

(ख) सभी अनियंत्रित पोशाकों/बूनों हुई मदों के लिए उद्यगम का प्रमाण-पत्र।

(2) फिनलैंड नियंत्रित मदों के लिए नियर्त प्रमाण-पत्र

(3) नियंत्रित अधिकारी अनियंत्रित को छोड़कर आस्त्रिया शक्ति चार्ज-त सूतं वस्त्र मिल से बनी हुई पोशाकों के लिए नियर्त प्रमाण-पत्र।

(4) कोनाडा सलाई से बनी हुई सवित चालित और मिल मिश्रित उद्यगम की पोशाकों के लिए नियर्त प्रमाण-पत्र किन्तु जो नियंत्रण के अधीन है उन्हें छोड़कर 500

14. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Maharashtra, Bombay.
15. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Manipur, Imphal.
16. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Meghalaya, Shillong.
17. Minister in charge of Handlooms & Government of Nagaland, Kohima.
18. Minister in charge of Handlooms & Government of Orissa, Bhubneswar.
19. Minister in charge of Handlooms & Government of Punjab, Chandigarh.
20. Minister in charge of Handlooms & Government of Rajasthan, Jaipur.
21. Minister in charge of Handlooms & Government of Sikkim, Gangtok.
22. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tamil Nadu, Madras.
23. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tripura, Agartala.
24. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
25. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of West Bengal, Calcutta.
26. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Pondicherry, Pondicherry.
27. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Mizoram, Aizawl.
28. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar.
29. Secretary to the Government of India, Department of Textiles, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
30. Financial Adviser, Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
31. Adviser (Village & Small Scale Industries), Government of India, Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
32. Secretary, Industries Department, Delhi Administration Kashmere Gate, New Delhi.
33. Development Commissioner (Small Scale Industries), Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
34. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, 4-Siri Institutional Area, Hauzkhast, New Delhi.
35. Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development, Post Box No. 6552, Dr. Anne Basant Road, Bombay-18.
36. Chairman, North Eastern Handicrafts & Handlooms Development Corporation, Bomfyl Road, Shillong.
37. Chairman, Khadi & Village Industries Commission, 3, Irla Road, Ville Parle, Bombay (West).
38. Managing Director, Handlooms & Handicrafts Export Corp., Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
39. Shri Ashok Chatterjee, Director National Institute of Design, Paldi, Ahmedabad.
40. Smt. Mrinalini Sarabhai, 'Chidambaram' Ahmedabad-380013.
41. Prof. K. G. Subramaniam, Viswa Bharati University, Shantiniketan, West Bengal-731235
42. Dr. Kamala Chowdhary, Apartment-2A, 33-Prithviraj Road, New Delhi.
43. Shri Martand Singh, 'Gulmarg' Shekhawat, Ahmedabad-380004.
44. Shri Ghulam Sheikh, Faculty of Fine Arts, University of Baroda, Baroda.
45. Shri Rajeev Sethi, C-4, Niti Bagh, New Delhi.
46. Shri Sankha Chowdhury, G-34, East of Kailash, New Delhi.
47. Smt. Lotika Varadarajan, 74, Sunder Nagar, Ground floor, New Delhi-2.
48. Shri Charles Correa, 9 Mathew Road, Bombay.
49. Shri Har K. Watal, Kailash Carpets, Dvipur House, Agra.
50. Dr. Jyotiindra Jain, 1, Ambika Society, Usmanpura, Ahmedabad.
51. Smt. Prema Srinivasan, West side House No. 2, Adayar Club Gate Road, Madras-600028.
52. Smt. Homi J. Talyarkhan, Raj Bhawan, Gangtok, Sikkim.
53. Shri M. P. Nachimuthu, President Chennimalai Weaver's Cooperative Society Ltd., Chennimalai, Tamil Nadu.
54. Shri P. Rajagopal Naidu, President, Tribuvananam Silk Handloom Weavers Cooperative Society Ltd., Tribuvananam, P.O. Thanjavur Distt. Tamil Nadu.

- FMD|Bank Guarantee furnished by him for quantities so surrendered.
- (ii) In the case of FCFS Small Orders and Central|State Corporations Systems, an exporter shall be required to give earnest money deposit|performance bond backed by Bank Guarantees at the rate of 10 per cent of the F.O.B. value of the quantities applied for.
  - (iii) For the slow-moving items identified as such under the provisions of this Scheme, nominal Earnest Money Deposits prescribed by the Textile Commissioner would be required in place of FMD|Bank Guarantees as mentioned above.
  - (iv) An exporter, who exports not less than 90 per cent of the export entitlement allotted to him within the whole year under Past Performance or Manufacturer Exporter Systems, or in a particular period under other systems of allotment, will not be liable to forfeiture of EMD|Bank Guarantees. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If the utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of his EMD|Bank Guarantee in full. This will be subject to conditions of force majeure, wherever these arise.
  - (v) In the case of Central|State Corporations where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for extension should be filed within one month of the end of the relevant export entitlement period. This provision will apply in the case of slow moving items under the FCFS Small Orders System. In such cases, the exporter will have to furnish EMD|Bank Guarantee at double the normal rate for the balance quantity. In case of his failure to export fully the EMD|Bank Guarantee will be liable to be forfeited in full.
  - (vi) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting export entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

**7. Appeal Against Forfeiture of EMD|Bank Guarantees**—For the purpose of giving due consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMD|Bank guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD|Bank guarantees by the Apparels Export Promotion Council, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

**8. Merger of Available Quantities from 1st October, 1983**—Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice and Publ/ce No. 1, e. No. 37-ETC(PN)/82 dated the 18th September, 1982, all balances of quantities available as on 1st of October, 1983 from unallocated levels or surrenders shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the FCFS Small Orders System without any reservation for different segments.

**9. Supervision of Allocation of Export Entitlements**—The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion the decision of the Textile Commissioner will be final.

#### 10. Clearance by Customs :

**A. Products under restraint**—Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Apparels Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

**B. Handloom garments**—In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and cotton handloom garments to Austria are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of "Inspection Endorsement" by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form. In the case of exports of handloom garments to USA, EEC and Finland, Customs will permit shipments after verification of certification by the Textiles Committee as to the handloom origin of the goods.

**C. Garments falling under "India Items"**—In respect of "India Items" which are traditional folklore handicrafts textile products of India, shipment will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

**11. A Export Certificate, Certificate of Origin and Visa**—The following certification required under the relevant bilateral textile agreement will be issued by the Apparels Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :

- (i) EEC—(a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment|knitwear items under restraint ;  
(b) Certificates of origin for all non-restrained garments|knitwear items.
- (ii) FINLAND—Export Certificates for restrained items.
- (iii) AUSTRIA—Export Certificates for cotton powerloom|mill-made garments subject to restraint or surveillance.
- (iv) CANADA—Export Certificates for garments of knitted, powerloom and millmade origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian \$ 500 or less
- (v) U.S.A.—(a) VISA for all garment|knitwear consignments valued over US \$250.  
(b) Exempt Certification for consignments valued at US \$ 250 or less

**11.B. Handloom Certificate**—In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of cotton handloom garments to Austria, the Textile Committee will issue the certificates as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

12. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

13. The address of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows

1. The Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019

2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/14, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

3. Office of the Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400020.

4. Textile Committee, 'Crystal' 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.

5. Development Commissioner, (Handicrafts) West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller  
of Imports & Exports